

Mot - 1  
17/21  
152

13.07.21

कार्यालय हाजा की रिट शाखा में प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में विचारधीन एस.बी. सिविल रिट पेटिशन संख्या 3608/2021 के साथ संलग्न स्नेक्सर-7 के अवलोकन पश्चात् न्यायालय के स्वतः संज्ञान स्वरूप पत्रावली निर्धारित तारीख वेगी से पूर्व प्रस्तुत हुई। उक्त रिटयाधिका संख्या 3608/2021 के अवलोकन से न्यायालय हाजा के संज्ञान में आया कि हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि चक 16 एपीडी (ए) तहसील अनूपगढ़ के मुख्वा नं. 262/391 की 25 बीघा भूमि उपायुक्त उपनिवेशन राजस्थान केनाल परियोजना, बीकानेर द्वारा दिनांक 21.08.1965/07.08.1965 को प्राथीगण के पिता कालासिंह पुत्र कानसिंह को अर्पित की गई थी। स्वतः आवंतन के पश्चात् कुछ व्यक्तियों द्वारा उक्त आवंतन के संबंध में तथ्य छुपाकर गलत तरीके से अर्पण करवाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। उक्त शिकायत की विस्तृत जांच पश्चात् उपायुक्त उपनिवेशन, श्रीविजयनगर द्वारा गलत तथ्य के आधार पर भूमि आवंतन करवाना सिद्ध मानते हुए प्राथीगण के पिता कालासिंह पुत्र कानसिंह का आवंतन अपने निर्गम दिनांक 21.02.1976 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

प्रश्नगत भूमि के आवंटन निरस्तता का उक्त आदेश प्रथम अपील, द्वितीय अपील, निगरानी, रिट याचिका आदि के माध्यम से समय-समय पर चैलेन्ज किया गया जो कि अतिरिक्त उपनिवेशन कायुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर, माननीय न्यायालय राजस्वमण्डल, अजमेर, राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा यथावत् रखा गया।

दिनांक 19.07.18 को माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में विचारित एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2366/2019 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.19 द्वारा प्रार्थीगण की रिट याचिका अन्तिम रूप से खारिज की जा चुकी है एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अपने उक्त निर्णय में यह अभिव्यक्ति किया है कि याचिकाकर्ताओं को प्रश्नगत भूमि का कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है।

अतः उपर्युक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में आंकटित रकबा खारिजी से संकक्ष तथ्य के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य या विभिन्न अपीलोज न्यायालयों में कोई अनुतोष न प्राप्त होने एवं माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा रखने का कोई विधिक अधिकार न होने का अभिनिर्धारण, न्यायालय हाजा के समक्ष उद्घाटित नहीं किए गए। अतः के क्रम में न्यायालय का मानना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण से संबंधित तथ्यों को छुपाते हुए न केवल हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वरन् न्यायालय से स्थगन आदेश अन्तरिम भी प्राप्त किया है। फलतः स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष न आने के कारण न केवल प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है, वरन् हस्तगत प्रार्थनापत्र भी घोषणीय नहीं है।

अतः वकील प्रार्थीगण 3 दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुकम

23.07.21 को न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न उपर्युक्त विवेचित आधारों पर हस्तगत प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया जावे। आगामी तारीख पेशी बाबत वकील प्रार्थना को नोट करवाया जावे। पत्रसूची दिनांक 23.07.21 को पेश हो।

*[Signature]*  
13/07/21

23/7/21

पत्रसूची बाबत। वकील प्रार्थना उपर्युक्त वकील प्रार्थना न्यायालय के समक्ष ही गई वकील के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने में कलम रखे। कतः हस्तगत प्रार्थनापत्र न्यायालय के द्वारा अभी उत्तर पर नामसूची भिजा जात है। पत्रसूची विफलापुत्रा दायित्व दफ्तर केरत नम्बर के रूप है।

(पवन कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़